MAINTENANCE

भानु प्रताप सिंह
वित्त अधिकारी

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ– 226031

पत्रांक [illegible] /डा0ए0के0टी0यू/वित्त समिति/वित्त मु0/2017

दिनांक 09-08-17

सेवा में,

निदेशक

1. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर।
2. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर।
3. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा।
4. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी।
5. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।
6. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।
7. यू.पी.टी.टी.आई., कानपुर।
8. बी.आई.ई.टी., झाँसी।
9. के.एन.आई.टी., सुल्तानपुर।
10. कुलसचिव, एच.बी.टी.यू., कानपुर।
11. कुलसचिव, एम.एम.एम.टी.यू., गोरखपुर।

महोदय,

इस पत्र के साथ दिनांक 02.08.2017 को सम्पन्न डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ की, वित्त समिति की 48वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 17:48:10 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(भानु प्रताप सिंह)
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि :- स्टाफ आफिसर, कुलपति, ए.के.टी.यू., लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(भानु प्रताप सिंह)
वित्त अधिकारी

FC

AC-2e
10/8/17

Scanned by CamScanner

[illegible]

शासकीय इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य प्राविधिक [illegible] हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर राज्य प्रवेश परीक्षा निधि की बचतों से प्राप्त संग्रहित निधि से रु.200.00 करोड़ की सहायता दी जानी प्रस्तावित है। इसमें 10 शासकीय इंजीनियरिंग कालेजों विश्वविद्यालय के घटक संस्थान आई.ई.टी., लखनऊ, वास्तुकला संकाय, लखनऊ तथा यू.पी.इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नोएडा, सेन्टर ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.के. टी.यू., लखनऊ तथा दो अन्य प्राविधिक विश्वविद्यालयों (एम.एम.एम.टी.यू., गोरखपुर, एच.बी.टी.यू., कानपुर) को सहायता दी जानी प्रस्तावित है। इस योजना के मूल उद्देश्य निम्नवत हैः-

इस योजना में निर्धारित धनराशि में से 60% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट एवं नव निर्माण, 40% धनराशि डिजिटलीकरण, शोध एवं रोजगार को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय की जायेगी।

1. चयनित संस्थाओं में इंफास्ट्रक्चर, नये निर्माण, प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण व उच्चीकरण।

कक्षाओं की संख्या, स्मार्ट कक्षाओं की संख्या, प्रयोगशालाओं, हॉस्टल्स, आवासों की संख्या में वृद्धि, खेल-कूद की सुविधाओं में वृद्धि।

2. शोध को बढावा देना।

शोध पत्रों का प्रकाशन, एम.टेक./पी.एच.डी. गाइडेड, पेटेन्ट्स की संख्या।

3. अक्षय ऊर्जा के उपोग को बढावा देना।

सोलर प्लांट

4. छात्र-छात्राओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना व ट्रेनिंग व प्लेसमेन्ट सेल का सुदृढीकरण

स्थापित छात्रा-छात्राओं की संख्या अधिकतम/न्यूनतम औसत पैकेज, कम्पनीज की संख्या जिन्हों ने छात्रों का चयन किया, छात्र-छात्राओं की संख्या जो कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया।

5. ई-संसाधनों का विकास

ई-फीस कलेक्शन, ई-टेण्डर नीलामियों में बढ़ोत्तरी, मूल्य का कम होना, गुणवत्ता में सुधार होना।

6. दिव्यांगों हेतु सुविधाओं का विकास।

रैम्प्स/दिव्यांगों हेतु शौचालय व एस्केलेटरों की संख्या में वृद्धि

क्रमांक	संस्था का नाम	अवमुक्त की जानी वाली धनराशि
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ	रु.25.00 करोड़
2.	कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,	रु.15.00 करोड़

Scanned by CamScanner

[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	फैकल्टी ऑफ आर्कीटेक्चर, ए.के.टी.यू., लखनऊ।	रु.10.00 करोड
6.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बाँदा।	रु.10.00 करोड
7.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर।	रु.10.00 करोड
8.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़।	रु.10.00 करोड
9.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर।	रु.10.00 करोड
10.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।	रु.10.00 करोड
11.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी।	रु.10.00 करोड
12.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।	रु.10.00 करोड
13.	उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ए.के.टी.यू., नोएडा।	रु.10.00 करोड
14.	सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.के.टी.यू. लखनऊ।	रु.15.00 करोड

2. अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	अवमुक्त की जानी वाली धनराशि
1.	मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर।	रु.15.00 करोड
2.	हरकोर्ट बटलर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कानपुर।	रु.15.00 करोड

यह योजना तीन वर्षो की होगी, जिसमें कुल रु.200.00 करोड की धनराशि उत्तर प्रदेश की सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिये संस्थाओं को पी.एफ.एम.एस. में पंजीयन कराना होगा और सीधे भुगतान किया जाएगा। सभी खरीद ई-टेण्डर अथवा जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। सभी अनुरक्षण कार्य ई-टेण्डर के माध्यम से की जायेगी। सभी नये निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास विकास निगम लिमिटेड इत्यादि के माध्यम से कम्पटीटिव बिल्डिंग के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के ग्राण्ट इन एड के लिये निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जायेगा और व्यय हेतु बजट में मैनुअल में निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त योजना की धनराशि विश्वविद्यालय के रेगुलेशन 4.26(II) के अन्तर्गत

[illegible] का अनुमोदन प्राप्त [illegible] अनुदान [illegible] तथा [illegible] संचालित [illegible] विश्वविद्यालयों [illegible] म [illegible] विभाग निर्णय तथा तदनुसार विश्वविद्यालय के विनियम में वांछित संशोधन किये जाने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। (यहाँ यह अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय बनने से पूर्व यह संस्थायें ए.के.टी.यू., लखनऊ से सम्बद्ध शासकीय संस्थायें के रूप में कार्यरत थी अत: इन संस्थाओं को भी राज्य प्रवेश परीक्षा की बचतों से सहायता दिया जाना उचित होगा।) कार्यवाही कुलसचिव / वित्त अधिकारी

मद संख्या 17:48:11 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव पर विचार।**

1. वित्त समिति के मद संख्या 17:48:10 के सम्बन्ध में शासकीय संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेपित किये गये सुझाव वित्त समिति के अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इन सुझावों के अनुसार धनराशि का आवंटन तथा अवमुक्त किया जाना शासन से अनुमोदन के उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निर्णय कार्यवृत्त के पूर्व मद 17:48:10 पर प्रस्तुत किया जा चुका है। कृपया तद्नुसार ही कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

2. भवन निर्माण समिति की 19वीं बैठक के मद संख्या 19.09 के निर्णयानुसार कुछ कक्षों में स्प्लिट ए.सी. निर्माण संस्था के माध्यम से लगाये जाने तथा प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर स्थिति सभागार में पब्लिक एडरेस सिस्टम लगाये जाने का कार्य निर्माण संस्था के माध्यम से कराये जाने तथा इसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा सेन्टेज छोड़ते हुये किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

स्प्लिट ए.सी. के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय पूर्व में आई.ई.टी., लखनऊ के जिस कैम्पस में संचालित था उसमें से जिस ए.सी. की आवश्यकता नहीं है तथा यू.पी.एस.ई.ई. तथा गेस्ट हाउस से निकले पुराने ए.सी. को प्रयुक्त किया जायेगा। शेष प्रस्ताव अनुमोदित किया गया गया। कार्यवाही कुलसचिव

3. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज आजमगढ़ तथा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज का आय-व्ययक वर्ष 2017-18 अनुमोदित किया गया।

(भानु प्रताप सिंह)
सदस्य-सचिव/वित्त अधिकारी

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
अध्यक्ष/कुलपति

Scanned by CamScanner